अरुण कुमार एवं अन्य।

बनाम

भारत संघ और अन्य।

3 अप्रैल 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे]

सेवा कानून:

पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959:

नियम 2(बी) और 14 नियुक्ति-प्रतिनियुक्ति अधिकारी का संवर्ग में समामेलन शुद्धता-निर्धारित नियमों की सख्त व्याख्या पर, प्रतिनियुक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन यह अपवादित मामलों में हो सकता है-ऐसे मामलों में समामेलन के लाभ को गलत नहीं ठहराया जा सकता है यदि वह एक सदभाविक प्रयास है।

नियम 2(बी), 13 और 14- सी.आर.पी.एफ. में सहायक कमांडेंट को पंजाब पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर पंजाब पुलिस में डिप्टी एस.पी. के रूप में उसकी सेवा को उस तारीख से नियमित करना जब वह सी.आर.पी.एफ. में नियुक्त हुई थी, न कि उस तारीख से जब वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुई थी-शुद्धता सी.आर.पी.एफ. और पंजाब पुलिस सेवा को नियंत्रित करने वाले सर्विस नियम अलग-अलग थे, और कार्यात्मक रूप से भी, दो कैडर अलग-अलग थे, पुलिसिंग के अलावा, पंजाब पुलिस सेवा के अधिकारी को अपराध की जांच करनी होती थी और सीआरपीसी, आईपीसी आदि का ज्ञान होना चाहिए, जो सी.आर.पी.एफ. में आवश्यक नहीं था-इसके अलावा, उसका

समामेलन डिप्टी एस.पी. के पद पर वरिष्ठता से संबंधित था क्योंकि उस वरिष्ठता को अंततः पदोन्नति के लिए गिना जाता था। अगले उच्च कैडर के लिए - नियमों के अभाव में, सीआरपीएफ में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है, यहां तक कि अपवादित मामले में भी क्योंकि प्रतिनियुक्ति पंजाब पुलिस में भर्ती का स्रोत नहीं था - नियम 14 को अनुपयुक्त पाया गया क्योंकि इसमें एक के अस्तित्व पर विचार किया गया था। भर्ती का नियम, और चूंकि भर्ती के स्रोत के रूप में प्रतिनियुक्ति का प्रावधान करने वाला कोई नियम नहीं था, सरकार एक गैर-मौजूद नियम में ढील नहीं दे सकती थी - हालांकि, पंजाब पुलिस सेवा में उनके अनुभव एक्स डिप्टी एस.पी. को उचित महत्व देने का आदेश दिया गया।

नियुक्ति-अनुकंपा आधार-पंजाब पुलिस सेवा में आईपीएस अधिकारी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी-उनकी बहन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में यह ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया गया कि यह पंजाब पुलिस सेवा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थी और चूंकि वह अपने बूढे माता-पिता की एकमात्र संतान थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। ऐसा निर्धारित किया गया कि उसकी नियुक्ति अनुकम्पा नियुक्ति न होकर अपवादित नियुक्ति थी।

वरिष्ठता-अंतर-निर्धारण-निर्धारित- समानता की अवधारणा को निरधारण होना चाहिए-उन लोगों के अधिकार भारत संविधान 1950के अनुच्छेद 14 और 16(1)को ध्यान में रखकर जो सेवा में रहे हैं और जो

कैडर में वरिष्ठता और पदोन्नति के हकदार भी है ।

प्रतिनियुक्ति- निर्धारित किया -प्रकृति-यह स्थानांतरण के समान है, प्रत्यक्ष नियुक्ति के समान नहीं।

प्रतिवादी नं. 4 पंजाब पुलिस सेवा के एक आईपीएस अधिकारी की बहन है जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उस घटना के कारण उन्हें 9.6.1989 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कार्यभार उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि यह पंजाब पुलिस सेवा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था। उनकी नियुक्ति सीआरपीएफ नियमों द्वारा शासित थी। उनकी परिवीक्षा पूरी होने पर, उन्हें 16-17.8.1993 को पंजाब पुलिस में पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11.9.1998 तक सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा, जब उन्हें पंजाब पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया। उन्हें 9.6.1989 से वेतन और वरिष्ठता सहित सभी लाभ दिए गए। इसी बीच, उन्हें मार्च, 1995 में सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया।

अपीलकर्ता पंजाब पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 के समामेलन को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, लेकिन उसे ही बर्खास्त कर दिए गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि (i) प्रतिवादी संख्या 4 का समामेलन में पंजाब पुलिस के पास कानूनन अधिकार नहीं था और वह भारत के

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 16(1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, विशेष रूप से सरकार द्वारा उन्हें वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के मद्देनजर 9.6.1989 से; (ii) वह अनुकंपा के आधार पर सीआरपीएफ में नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर ही पंजाब पुलिस सेवा में दोबारा शामिल होने के दोहरे लाभ की हकदार नहीं थी; (iii) पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के तहत प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है; (iv) सीआरपीएफ अपनी गतिविधियों में कानून और व्यवस्था तक ही सीमित है जबकि पंजाब पुलिस के कार्यों में पुलिसिंग के अलावा अपराध का पता लगाने की भी आवश्यकता होती है; प्रतिवादी संख्या 4 ने आवश्यक प्रशिक्षण नहीं लिया था; (v) राज्य सरकार ने प्रतिवादी संख्या 4 की 1959 के नियमों के तहत 16/17.8.1993 और 11.9.1998 के बीच एसीआर नहीं रखी है, क्योंकि उनके पास सीआरपीएफ में एक पद के लिए ग्रहणाधिकार था; उपरोक्त अवधि के दौरान उनका संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड सीआरपीएफ नियमों द्वारा शासित था।

प्रतिवादी-राज्य सरकार ने तर्क दिया कि (i) प्रतिनियुक्ति 1959 के नियम 13 के साथ पढ़े गए नियम 2 (बी) के तहत सीधी नियुक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है, और राज्य नियम 14 में विचारित छूट के नियम को लागू करने का हकदार था; (ii) प्रतिवादी संख्या 4 के समामेलन पर 1998 में पंजाब पुलिस में डिप्टी एस.पी. के रूप में वह 9.6.1989 से सीआरपीएफ में अपने अनुभव का लाभ पाने की हकदार थीं।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1. सुश्री अमृत बराड़ को 9.6.1989 को सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार शुरू में उन्हें सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करने में सही थी, क्योंकि 1989 में राज्य में आतंकवाद अपने चरम पर था और सहायक कमांडेंट के रूप में उनकी पोस्टिंग पंजाब पुलिस में उनकी पोस्टिंग की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। वह अपने बूढ़े माता-पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए, उसकी रक्षा की जानी थी। हालाँकि, इससे उसकी नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति नहीं होकर एक अपवादित नियुक्ति थी। इस संबंध में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। [पैरा 8] [715-बी-सी]

2.1. स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें पंजाब पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया। यह 1993 में था। [पैरा 8] [715-सी-डी]

2.2. हालाँकि, उक्त 1959 नियम सामान्य कैडर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं करते हैं, सरकार, असाधारण मामलों में, पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कर सकती है। यह एक ऐसा मामला है। सुश्री अमृत बराड़ को पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने में राज्य सरकार की कार्रवाई में कोई खामी नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में वह उन लाभों की हकदार है। [पैरा 8] [715-डी-ई]

2.3. इसके अलावा, सुश्री अमृत बराड़ 11.9.1998 को डिप्टी एस.पी. के रूप में पंजाब पुलिस सेवा में शामिल हो गईं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसका समामेलन भी शिथिलता देने पर किया गया है। यह एक

अपवादित मामले में एक बार के प्रयास के माध्यम से था। [पैरा 8] [715-ई-एफ]

2.4. उक्त 1959 नियमों की कड़ाई से व्याख्या करने पर, भर्ती की तीसरी पद्धति खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उक्त 1959 नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। यह केवल एक असाधारण मामले के रूप में है कि प्रतिवादी नं. 4 को पंजाब पुलिस सेवा में डिप्टी एस.पी. के रूप में समामेलन का लाभ दिया गया और उस प्रयास में कोई दोष नहीं है। यह एक सदभाविक प्रयास है।[पैरा 12] [720-जी-एच; 721-ए]

3.1 हालाँकि, जब उसकी सेवाएँ राज्य द्वारा 16/17.8.1993 से नियमित नहीं की जाती हैं, जब वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुई थी, लेकिन 9.6.1989 से, जब वह सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुई थी, तो राज्य सरकार की कार्रवाई में दुर्बलता आ गई। [पैरा 12] [721-ए-बी]

3.2. सीआरपीएफ के कार्यों की तुलना पंजाब पुलिस सेवा से नहीं की जा सकती। पंजाब पुलिस सेवा के एक अधिकारी को पुलिसिंग के अलावा अपराध का पता लगाने की जांच का काम भी करना पड़ता है, जो सीआरपीएफ के दायरे में नहीं है। सीआरपीएफ में एक डिप्टी एस.पी. को सीआरपीसी, आईपीसी आदि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जो पंजाब पुलिस सेवा के एक अधिकारी के पास होना चाहिए। सीआरपीएफ को नियंत्रित करने वाले सेवा नियम पंजाब पुलिस सेवा को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों से भिन्न हैं। इसलिए, कार्यात्मक रूप से भी, दोनों कैडर

अलग-अलग हैं। वास्तव में, प्रतिवादी नं. 4, ने पंजाब पुलिस सेवा नियमों के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं लिया है। [पैरा 12] [721-बी-सी]

4.1. वर्तमान मामला अपीलकर्ताओं के अधिकारों से संबंधित है। यह डिप्टी एसपी के उक्त पद में परस्पर वरिष्ठता से संबंधित है क्योंकि वह वरिष्ठता अंततः अगले उच्च कैडर में पदोन्नति के लिए मायने रखती है। डिप्टी एस.पी. का पद इस अर्थ में एक फीडर पद है और जब पद एक फीडर पद होता है, तो परस्पर वरिष्ठता की भूमिका होती है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, तो इस प्रकृति के असाधारण मामलों में भी, नियमों के अभाव में, सीआरपीएफ में सुश्री अमृत बराड़ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को महत्व नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 12] [721-डी-एफ]

4.2. जब परस्पर वरिष्ठता तय करनी हो तो समानता की अवधारणा को ध्यान में रखना होगा। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14 के मूल सिद्धांत हैं। अपीलकर्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखना होगा, जो सेवा में रहे हैं और जो कैडर में वरिष्ठता और पदोन्नति के भी हकदार हैं। [पैरा 9]

5.1. प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के समान है, लेकिन सीधी नियुक्ति के समान नहीं। इस हद तक, आक्षेपित निर्णय में दुर्बलता है। [पैरा 11] [720-एफ]

के. माधवन और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य [1987] 4

एससीसी 566, के संदर्भ में।

5.2. नियम 14 में छूट की बात कही गई है। हालाँकि, नियम 14 उन नियमों पर लागू नहीं होता है जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती का प्रावधान नहीं करते हैं। नियम 14 लागू होता यदि उक्त 1959 नियमों में भर्ती का तीसरा स्रोत, अर्थात् प्रतिनियुक्ति होता। भर्ती का ऐसा कोई तीसरा स्रोत नहीं है. इसलिए, नियम 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। नियम 14 में नियमों में ढील देने का जिक्र है. नियम 14 भर्ती के एक नियम के अस्तित्व पर विचार करता है। अगर भर्ती के तीसरे स्रोत के लिये ऐसा कोई नियम नहीं है तो सरकार छूट नहीं दे सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति को भर्ती का तीसरा स्रोत मानने में गलती की थी। [पैरा 12] [721-एफ-जी]

6. सुश्री अमृत बराड़ ने 16/17.8.1993 और 11.9.1998 के बीच पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति के रूप में 5 साल की सेवा की है। वह निश्चित रूप से इन 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेटेज की हकदार हैं। [पैरा 12] [722-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4325/2006

1996 के सीडब्ल्यूपी संख्या 11548 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए गुरमिंदर सिंह, अजय पाल, निखिल जैन, गंगदीप शर्मा और महेश बाबू।

पी.एस. पटवालिया, जवाहर लाल गुप्ता और राजू रामचन्द्रन, अमन प्रीत सिंह राही, इंद्रा साहनी, सुषमा सूरी, संजय जैन, अरुण के. सिन्हा और एस. जनानी प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

कपाड़िया, जे. 1. इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए एक छोटा प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य सरकार पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 (छूट की शक्ति से संबंधित) के नियम 14 को लागू कर सकती थी, जबकि इसमें कोई प्रावधान नहीं था। पंजाब पुलिस सेवा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ("सीआरपीएफ") से स्थायी आधार पर प्रतिनियुक्तिकर्ताओं के समामेलन के लिए नियम।

2. इस सिविल अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं।

3. श्री अविन्दर सिंह बराड़, आईपीएस की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। वह पंजाब पुलिस सेवा में अधिकारी थे। उपरोक्त घटना के कारण, उनकी बहन, सुश्री अमृत बराड़-प्रतिवादी सं. 4, 9.6.1989 को दो साल के लिए परिवीक्षा पर सीआरपीएफ में जी सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुए। उपरोक्त दुखद परिस्थितियों में उन्हें सीआरपीएफ में नियुक्त किया गया था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उन्हें सीआरपीएफ में नियुक्त किया गया था क्योंकि पंजाब पुलिस सेवा की तुलना में सीआरपीएफ में उनका कार्यभार अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था। ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दर्शाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति दयालु नहीं बल्कि अपवाद स्वरूप थी। उनकी नियुक्ति सीआरपीएफ नियमों द्वारा शासित होनी

थी। वह दो वर्ष पूरे होने पर यहां परिवीक्षा पूरी की गई। 16/17.8.1993 को, सुश्री अमृत बराड़ को पंजाब पुलिस में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11.9.1998 तक सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा, जब उन्हें पंजाब पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया। उन्हें 9.6.1989 से वेतन और वरिष्ठता सहित सभी लाभ दिए गए। इस बीच, मार्च, 1995 में सुश्री अमृत बराड़ को सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया।

4. यहां अपीलकर्ता पंजाब पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। कुछ अपीलकर्ता पंजाब राज्य में आतंकवाद से लड़ने के लिए वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के प्राप्तकर्ता हैं। अपीलकर्ताओं ने सुश्री अमृत बराड़ को समामेलन देने के राज्य सरकार के आदेशों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी, विशेष रूप से इस आधार पर कि पंजाब पुलिस सेवा नियमों में सीआरपीएफ से प्रतिनियुक्ति अधिकारी को शामिल करने पर विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर समामेलन को चुनौती दी कि सुश्री अमृत बराड़ को 1989 में सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया गया था और इसलिए, वह 1998 में अनुकंपा समामेलन के दोहरे लाभ की हकदार नहीं थीं और वह भी 9.6.1989 से । अपीलकर्ताओं! उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य शिकायत यह थी कि 9.6.1989 से सुश्री अमृत बराड़ को वरिष्ठता का लाभ देने से वह लगभग दस अन्य अधिकारियों से वरिष्ठ हो जाएंगी।

अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ को दी गई वरिष्ठता के परिणामों का मतलब अपीलकर्ताओं का अधिक्रमण होगा। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ को अनुकंपा के आधार पर सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था और इसलिए, लगभग नौ वर्षों के बाद राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति के दूसरे प्रयोग का कोई कारण नहीं था। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष आगे कहा कि सीआरपीएफ सहित विभिन्न अर्धसैनिक बलों से पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कई अधिकारी थे, जिनमें से अधिकांश सुश्री अमृत बराड़ से पहले भी प्रतिनियुक्ति पर आए थे। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया कि, वास्तव में, राज्य सरकार ने पंजाब अर्धसैनिक बलों (समूह ए) सेवा अधिकारियों के समामेलन नियम, 2005 को अधिसूचित किया था और उक्त नियमों के तहत, राज्य सरकार ने समामेलन के लिए पूर्व-कैडर पद बनाए थे। अर्धसैनिक बल के अधिकारी, जो पंजाब राज्य में प्रतिनियुक्ति पर थे और जिन्हें पंजाब पुलिस सेवा में समाहित किया जाना था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, यदि 9.6.1989 से वरिष्ठता का लाभ सुश्री अमृत बराड़ को दिया जाता है तो समामेलन के मामले में भी वह कई अन्य अधिकारियों से आगे निकल जाती।

5. दिनांक 24.1.2006 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी संख्या 11548/96 को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा मुख्य आधारों में से

एक आग्रह किया गया था कि 9.6.1989 से सुश्री अमृत बराड़ की सेवाओं को नियमित करना और पंजाब पुलिस सेवा में एक प्रतिनियुक्ति अधिकारी को समाहित करना भर्ती की एक अलग पद्धति के निर्माण के समान होगा। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उक्त नियमों के तहत भर्ती के केवल दो स्रोत थे, 80% पदोन्नति द्वारा और 20% सीधी भर्ती द्वारा। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त नियमों में "सीधी नियुक्ति" शब्द में प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति शामिल होगी और इसलिए, नियम 14 वर्तमान मामले पर लागू होता है। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता वर्तमान सिविल अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आये हैं।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से, यह आग्रह किया गया कि राज्य सरकार ने सुश्री अमृत बराड़ को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में समाहित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ को 9.6.1989 से प्रभावी सहायक कमांडेंट के रूप में सीआरपीएफ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 11.9.1998 को पंजाब पुलिस सेवा में शामिल होने तक सीआरपीएफ में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ को सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद से उप कमांडेंट के पद पर पदोन्नति भी दी गई थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 को कई रियायतें दी गईं सुश्री अमृत बराड़ को 1989 में अनुकंपा के

आधार पर सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था; पंजाब पुलिस में उनका पद सरकार के आदेश दिनांक 13.10.1997 द्वारा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया था और यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षा के नियमों में भी ढील दी गई थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ अनुकंपा के आधार पर सीआरपीएफ में नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर पंजाब पुलिस सेवा में फिर से शामिल होने के दोहरे लाभ की हकदार नहीं थीं। अपीलकर्ताओं के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पंजाब पुलिस सेवा में भर्ती का स्रोत नहीं है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, आक्षेपित निर्णय का प्रभाव भर्ती का एक और स्रोत खोलना था जो पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 ("1959 नियम") के तहत प्रदान नहीं किया गया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सीआरपीएफ अपनी गतिविधियों में कानून और व्यवस्था तक ही सीमित है जबकि पंजाब पुलिस के कार्यों में पुलिसिंग के अलावा अपराध का पता लगाने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ ने आवश्यक प्रशिक्षण नहीं लिया था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, जब सुश्री अमृत बराड़ को 16/17.8.1993 को पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था, तब एसीआर की भी जांच नहीं की गई थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सीआरपीएफ कर्मी सीआरपीएफ नियमों द्वारा शासित होते हैं। वे उक्त पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 द्वारा शासित नहीं हैं। उक्त 1959 नियमों के तहत, राज्य सरकार ने एसीआरएस भी बनाए नहीं रखा है सुश्री अमृत बरार के बीच 16/17.8.1993 और 11.9.1998 । इसका कारण यह है कि

सुश्री अमृत बराड़ के पास सीआरपीएफ में एक पद का ग्रहणाधिकार था। यही कारण है कि सुश्री अमृत बरार को एसीआर के आधार पर डिप्टी कमांडेंट के पद पर मार्च, 1995 में पदोन्नत किया गया। इसलिए, उपरोक्त अवधि के दौरान उनका पूरा सेवा रिकॉर्ड सीआरपीएफ नियमों द्वारा शासित था और परिणामस्वरूप, पंजाब पुलिस में उनका समामेलन कानून के अधिकार के बिना था और अनुच्छेद 14 के तहत सहपठित भारत के संविधान के 16(1), विशेष रूप से सरकार द्वारा उन्हें 9.6.1989 से वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के मद्देनजर अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।

7. राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के तहत भर्ती की पद्धति प्रदान की गई है। उक्त 1959 नियमों के तहत भर्ती के दो स्रोत हैं। स्रोतों में सीधी भर्ती शामिल है। राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि उक्त 1959 नियमावली में 'सीधी भर्ती' शब्द का अर्थ किसी भी पद्धति से नियुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतिवादियों के अनुसार, एक प्रतिनियुक्ति नियम 2(बी) को नियम 13 के अंतर्गत सीधी नियुक्ति की परिभाषा में आएगी। इन परिस्थितियों में, राज्य की ओर से आग्रह किया गया था कि एक बार प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सीधी नियुक्ति के अर्थ में आ जाती है, तो राज्य नियम में विचारित छूट के नियम 14 को लागू करने का हकदार है। सरकार के अनुसार दिनांक 13.10.1997 के पत्र द्वारा इस पद को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, नियम 6 जो प्रतियोगी

परीक्षा को संदर्भित करता है, में ढील दी गई और तदनुसार इस छूट पर, सुश्री अमृत बराड़ को 9.6.1989 से 1998 में पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी के रूप में शामिल कर लिया गया, जो राज्य सरकार करने की हकदार थी। राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि उनके शामिल होने पर, सुश्री अमृत बराड़ को पंजाब पुलिस में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया जाए। राज्य सरकार के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़ ने 16/17.8.1993 से प्रतिनियुक्ति पर पंजाब पुलिस में काम किया था। राज्य सरकार के अनुसार, सुश्री अमृत बराड़, जिन्होंने 9.6.1989 और 16/17.8.1993 के बीच सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट/डिप्टी एस.पी. के रूप में काम किया था और परिणामस्वरूप, 1998 में पंजाब पुलिस में डिप्टी एस.पी. के रूप में शामिल हो गईं, वह दिनांक 9.6.1989 से सीआरपीएफ में उनके अनुभव का लाभ लेने की अधिकारी थी। राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि सीआरपीएफ में भी सुश्री अमृत बरार का पदनाम डिप्टी एस.पी. था और सीआरपीएफ में डिप्टी एस.पी. के कर्तव्यों की प्रकृति और पंजाब पुलिस में डिप्टी एस.पी. के कार्य समान थे और इसलिए सुश्री अमृत बराड़ द्वारा सीआरपीएफ में डिप्टी एसपी के रूप में किए गए अनुभव और काम को पंजाब पुलिस सेवा में शामिल करते समय ध्यान में रखा गया। राज्य सरकार के अनुसार, नियम 14 को लागू करने पर, सुश्री अमृत बराड़ पिछली सेवा के लाभ की हकदार थीं और तदनुसार उन्हें 9.6.1989 से पंजाब पुलिस में वरिष्ठता दी गई, इसलिए, राज्य सरकार के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का कोई उल्लंघन या उल्लंघन

नहीं हुआ।

8. सबसे पहले, हम कह सकते हैं कि देश के बहादुर अधिकारी, श्री अविन्दर सिंह बराड़, आईपीएस, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि सुश्री अमृत बराड़ को 9.6.1989 को सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार शुरू में उन्हें सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करने में सही थी, क्योंकि 1989 में राज्य में आतंकवाद अपने चरम पर था और सहायक कमांडेंट के रूप में उनकी पोस्टिंग अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। उनकी पोस्टिंग पंजाब पुलिस में है। वह अपने बूढ़े माता-पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए, उसकी रक्षा की जानी थी। हालाँकि, इससे उसकी नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो सकी। यह एक अपवादित नियुक्ति थी। इस संबंध में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें पंजाब पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया। यह 1993 की बात है। हमें उपरोक्त परिस्थितियों में सुश्री अमृत बराड़ को पंजाब पुलिस सेवा में भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने में राज्य सरकार की कार्रवाई में कोई कमी नहीं दिखती। हम यह स्पष्ट करते हैं कि पंजाब पुलिस सेवा नियम भर्ती के दो स्रोतों का प्रावधान करते हैं। एक सीधी भर्ती द्वारा, दूसरा पदोन्नति के माध्यम से। हालाँकि, उक्त 1959 नियम सामान्य कैडर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं करते हैं, सरकार, अपवादित मामलों में, पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कर सकती है। यह एक ऐसा

मामला है। हमें सुश्री अमृत बराड़ को पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने में राज्य सरकार की कार्रवाई में कोई कमी नहीं दिखती। उपरोक्त परिस्थितियों में वह उन लाभों की हकदार है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सुश्री अमृत बराड़ 11.9.1998 को डिप्टी एसपी के रूप में पंजाब पुलिस सेवा में शामिल हो गईं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसका समामेलन शिथिलता प्रदान कर किया गया है। यह एक अपवादित मामले में एक बार के प्रयास के माध्यम से था। इसलिए, एकमात्र विवाद यह है कि क्या सुश्री अमृत बराड़ 9.6.1989 से वरिष्ठता के एक और लाभ की हकदार थीं।

9. भर्ती के स्रोत के रूप में सीधी नियुक्ति, भर्ती की पद्धति में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से भिन्न है। वर्तमान मामले में, विवाद पंजाब पुलिस में डीएसपी के कैडर, जो कि फीडर पोस्ट है, में आपसी विवाद के आसपास घूमता है। यदि 9.6.1989 से सुश्री अमृत बराड़ को वरिष्ठता दी जानी है तो वह उन अपीलकर्ताओं को हटा देती हैं, जिन्होंने राज्य में आतंकवाद के उन्मूलन में भी योगदान दिया है। यह अगला उच्च पद है जो अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी नं. 4 का लक्ष्य है। यह परस्पर वरिष्ठता है जो अपीलकर्ताओं और राज्य के बीच विवाद को जन्म देती है। जब परस्पर वरिष्ठता तय करनी हो तो समानता की अवधारणा को ध्यान में रखना होगा। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14 के मूल सिद्धांत हैं। हमें अपीलकर्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखना होगा, जो सेवा में रहे

हैं और जो कैडर में वरिष्ठता और पदोन्नति के भी हकदार हैं। हम यहां पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के नियम 2(बी), 6, 7, 8, 10, 13 और 14 उद्धृत कर रहे हैं।

> "2. परिभाषाएँ.-इन नियमों में, जब तक कि इसमें कोई प्रतिकूल बात न हो विषय या प्रसंग- (बी) 'सीधी नियुक्ति' का अर्थ है एक इंस्पेक्टर की पदोन्नति से अन्यथा की गई नियुक्ति।

6. भर्ती की विधि- (1) सेवा में भर्ती की जायेगी -

(i) पदोन्नति द्वारा अस्सी प्रतिशत इंस्पेक्टर का पद बनाते हैं, और बीस प्रतिशत सीधी नियुक्ति द्वारा: बशर्ते कि केवल वही इंस्पेक्टर प्रमोशन के पात्र होंगे जो- (ए) इंस्पेक्टरों के मामले में (दोनों को अधीनस्थ रैंक से पदोन्नत किया गया है और सीधे भर्ती) छह वर्ष की निरंतर सेवा मिली हो (कार्यवाहक और साथ ही मूल) निरीक्षक के पद पर; और

(बी) यदि वे अभियोजन निरीक्षक हैं, तो उन्हें अभियोजन निरीक्षक के पद पर आठ साल की निरंतर सेवा (स्थानापन्न और मूल दोनों) मिली हो।

(2) सरकार द्वारा सूची 'जी' में लाए गए निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी, जो आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा तैयार की गई पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले अधिकारियों की एक सूची होगी। एक समय में तैयार की गई इस सूची में नामों को उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित किया

जाएगा। यह सूची दो भागों में रखी जाएगी: भाग । (कार्यकारी लाइन के अधिकारियों के लिए) और भाग ॥ (अभियोजन लाइन के अधिकारियों के लिए)।

(3) सेवा में सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर की जाएगी। सरकार आयोग के परामर्श से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम और नियम बनाएगी। सरकार आयोग के परामर्श से। परीक्षा में मौखिकपरीक्षा शामिल होगी। मौखिक परीक्षा के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक से कम प्राप्त नहीं किये हैं। पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक साक्षात्कार में उपस्थित रहेंगे और उम्मीदवार से प्रश्न पूछने और आयोग के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के हकदार होंगे। किसी उम्मीदवार की स्थिति लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर निर्धारित की जाएगी। बशर्ते कि अन्य बातें समान हों, प्राथमिकता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए काम किया हो या कोई उत्कृष्ट सामाजिक या सार्वजनिक सेवा प्रदान की हो।

7. योग्यताएं किसी भी व्यक्ति को सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि-

(i) जिस वर्ष नियुक्ति की जानी है उस वर्ष की पहली फरवरी को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम और पच्चीस वर्ष से अधिक न हो;

(ii) वह पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड, भाग 1 के नियम 3.1 द्वारा

निर्धारित शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है;

(iii) उसकी न्यूनतम ऊंचाई 5'-7" और छाती का सामान्य माप 33" हो जो 1-1/2 " के विस्तार के साथ।

(iv) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और मैट्रिक या उसके समकक्ष मानक तक हिंदी और पंजाबी दोनों का ज्ञान रखता है।

बशर्ते कि उप-खंड (i) में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के मामले में तीस वर्ष होगी;

बशर्ते कि उप-खंड (iii) में निर्धारित भौतिक मानक को सरकार की विशेष मंजूरी के बिना शिथिल नहीं किया जाएगा

(2) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे;

बशर्ते कि यह अयोग्यता ऐसे मामले जहां ये 8 सितंबर, 1954 से पहले किया गया था, और भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी है में लागू नहीं होगी।

(3)(i) सरकार वर्ष के दौरान सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगी, और आयोग प्रस्तावित नियुक्तियों का प्रचार करने और आवेदन आमंत्रित करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम अधिसूचित होने से पहले आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स या समकक्ष परीक्षा

में उपस्थित होने वाले या उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अस्थाई आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) प्राप्त आवेदनों को जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब को जो ऐसी पूछताछ कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे और उसके बाद सभी आवेदन आयोग को अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो,वापस कर देगा।

(iii) आयोग प्राप्त सभी आवेदनों की जांच करेगा सभी को नियम 6 के उपनियम(3) में उल्लिखित परीक्षा में प्रवेश देगा जो उम्मीदवार इन नियमों के अनुसार पात्र पाए गए हैं।

(iv) परीक्षा में सफलता किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं देगी, जब तक कि सरकार आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

8.सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा.

(ए) सेवा के सदस्य दो साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, फिल्लौर और जिलों में प्रशिक्षण की अवधि शामिल होगी और पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में, सरकार प्रत्येक मामले में एक विशेष आदेश द्वारा, स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि को परिवीक्षा की अवधि में गिनने के लिए सेवा को अनुमति दे सकेगी।

(बी) सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किए गए सदस्य की सेवाएं उसके प्रशिक्षण की अवधि के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने

पर, नियुक्ति के लिए अयोग्य के रूप में या उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में रिपोर्ट किए जाने पर सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। बशर्ते कि यदि सरकार उचित समझे तो परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।

(सी) पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक को निरीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा नियुक्त परिवीक्षा पर सेवा के किसी भी सदस्य को प्रशिक्षण के एक विशेष पाठ्यक्रम से गुजरने और किसी भी विषय या विषय में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें अनिवार्य भाषा भी शामिल है जिसमें उसकी योग्यता दोषपूर्ण हो सकती है। ऐसा कोई भी परिवीक्षार्थी उसके लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है या उसकी प्रतिकूल रिपोर्ट की जाती है, तो उसे निरीक्षक के मूल पद पर वापस भेजा जा सकता है।

10. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता। सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता सेवा में पुष्टि की तिथि से निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि यदि एक ही तिथि पर दो या दो से अधिक सदस्यों की पुष्टि की जाती है।

(i) पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया सदस्य अन्यथा नियुक्त किए गए सदस्य से वरिष्ठ होगा।

(ii) उन सदस्यों के मामले में जो सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त किए गए थे, वरिष्ठता प्रतियोगी परीक्षा में उनकी स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

(iii) उन सदस्यों के मामले में जिन्हें पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया था, वरिष्ठता पदोन्नति सूची 'जी' में उनकी प्रविष्टि की तारीख के साथ तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

13. इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए मामले- इन नियमों में विशेष रूप से उल्लिखितनहीं किए गए सभी मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य ऐसे सामान्य नियमों द्वारा शासित होंगे जो इस संबंध में सरकार द्वारा भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत बनाए जा सकते हैं या इसके बाद बनाए जा सकते हैं।

14. नियमों में ढील देने की सामान्य शक्तियाँ- जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है।

10. राज्य सरकार की ओर से और प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से के. माधवन और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य, [1987] 4 एससीसी 566 में भारी निर्भरता रखी गई है। इस न्यायालय के फैसले पर में रिपोर्ट किया गया। उस मामले में याचिकाकर्ताओं, माधवन और सेन को क्रमशः 6.7.1963 और 10.8.1963 को सीबीआई में डीएसपी के रूप में सीधे भर्ती किया गया था। ओ.पी. शर्मा, प्रतिवादी संख्या. 5, जिन्हें 13.7.1962 को राजस्थान राज्य पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया था, 1.7.1967 को डीएसपी के रूप में सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उस समय, इस न्यायालय ने पाया सीबीआई में अधिकांश अधिकारी

प्रतिनियुक्ति पर थे। ओ.पी. शर्मा को 1.12.1964 को राजस्थान पुलिस सेवा में डीएसपी के रूप में पुष्टि की गई थी। 30.3.1967 को माधवन और सेन को सीबीआई में डीएसपी के रूप में पुष्टि की गई। दिनांक 17.10.1981 को सी.बी.आई. द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में ओ.पी. शर्मा का नाम, प्रतिवादी क्रमांक. 5, याचिकाकर्ताओं, माधवन और सेन के नामों के ऊपर दिखाया गया था। याचिकाकर्ताओं, माधवन और सेन ने परस्पर वरिष्ठता सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी नं. 5 सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर था और समामेलन पर वह राजस्थान पुलिस सेवा में अपनी सेवाओं के लाभ का हकदार नहीं था। इस तर्क पर, इस न्यायालय ने पैरा 19 के माध्यम से माना कि, सीबीआई में एसपी के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में सेवा की अपेक्षित अवधि की गणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान ओपी शर्मा, प्रतिवादी संख्या 5, राजस्थान राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे, को विचार में लिया जाना चाहिए।

11. इस पैरा पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 सुश्री अमृत बराड़, की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि सीआरपीएफ में उनकी सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और निर्णय परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में और वह 9.6.1989 और 16/17.8.1993 के बीच की सेवा के संबंध में वेटेज की हकदार थी। हालाँकि, के. माधवन (सुप्रा) के मामले में निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस न्यायालय ने सेवा नियमों की जांच की जिसमें भर्ती का तीसरा स्रोत था, अर्थात् स्थानांतरण, और इसलिए, पैरा 21 में, इस न्यायालय ने पाया कि, वहाँ प्रतिनियुक्ति और

स्थानांतरण के बीच कोई अधिक अंतर नहीं था, और चूंकि नियमों के तहत स्थानांतरण भर्ती का स्रोत था, इसलिए ओपी शर्मा राजस्थान राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए वेटेज के हकदार थे। माना कि वर्तमान मामले में स्थानांतरण भर्ती का तीसरा स्रोत नहीं है। इसके विपरीत, उपरोक्त निर्णय प्रतिनियुक्ति को स्थानांतरण के बराबर बताता है। यह प्रतिनियुक्ति को सीधी नियुक्ति के बराबर नहीं मानता जैसा कि आक्षेपित निर्णय में किया गया है। इस हद तक, आक्षेपित निर्णय में दुर्बलता है

12. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने फैसले में यह स्पष्ट करते हैं कि हमने पहले देखा है कि प्रतिवादी संख्या 4 को पंजाब पुलिस सेवा में डिप्टी एस.पी. के रूप में समाहित करने में राज्य सरकार की कार्रवाई में कोई कमजोरी नहीं दिखती है। हालाँकि, एक चेतावनी है। हमारे अनुसार, उक्त 1959 नियमों की सख्ती से व्याख्या पर, भर्ती के तीसरे तरीके को खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिनियुक्ति उक्त 1959 नियमावली के तहत भर्ती का स्रोत नहीं है। यह केवल एक अपवादित मामले के रूप में है कि प्रतिवादी नं. 4 को पंजाब पुलिस सेवा में डिप्टी एस.पी. के रूप में समामेलन का लाभ दिया गया और हमें उस अभ्यास में कोई दोष नहीं मिला। यह एक सदभाविक प्रयास है। हालाँकि, जब उनकी सेवाएँ राज्य द्वारा 16/17.8.1993 से नियमित नहीं की गईं, जब वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुईं, बल्कि 9.6.1989 से, जब वह सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुईं, तो राज्य की कार्रवाई में दुर्बलता आ गई।

सीआरपीएफ के कार्यों की तुलना पंजाब पुलिस सेवा से नहीं की जा सकती। पंजाब पुलिस सेवा के एक अधिकारी को पुलिसिंग केअलावा अपराध का पता लगाने की जांच का काम भी करना पड़ता है, जो सीआरपीएफ के दायरे में नहीं है। सीआरपीएफ में एक डिप्टी एस.पी. को सीआरपीसी, आईपीसी आदि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जो पंजाब पुलिस सेवा के एक अधिकारी के पास होना चाहिए। इसलिए, कार्यात्मक रूप से भी, दोनों कैडर अलग-अलग हैं। दरअसल, प्रतिवादी नं. 4, सुश्री अमृत बराड़ ने पंजाब पुलिस सेवा नियमों के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं लिया है। हालाँकि, उन्होंने 16/17.8.1993 और 11.9.1998 के बीच पंजाब पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी के रूप में 5 साल का अनुभव रखा है। उस अनुभव को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में, उपरोक्त पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। सीधी भर्ती ही स्रोत है। प्रमोशन ही एक जरिया है। हालाँकि, प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, हम अपीलकर्ताओं के अधिकारों से चिंतित हैं। हम डिप्टी एसपी के उक्त पद में परस्पर वरिष्ठता को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वह वरिष्ठता अंततः अगले उच्च कैडर में पदोन्नति के लिए मायने रखती है। डिप्टी एसपी का पद उस अर्थ में एक फीडर पद है और जब पद एक फीडर पद होता है, तो परस्पर वरिष्ठता की भूमिका होती है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि प्रतिनियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, तो इस प्रकृति के अपवादित मामलों में भी, नियमों के अभाव में, सीआरपीएफ में सुश्री अमृत बराड़ द्वारा प्रदान की

गई सेवाओं को महत्व नहीं दिया जा सकता है। नियम 14 में छूट की बात कही गई है। हालाँकि, नियम 14 उन नियमों पर लागू नहीं होता है जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती का प्रावधान नहीं करते हैं। नियम 14 लागू होता यदि उक्त 1959 नियमों में भर्ती का तीसरा स्रोत प्रतिनियुक्ति होता। भर्ती का ऐसा कोई तीसरा स्रोत नहीं है। इसलिए, नियम 14 का कोई उपयोग नहीं है। नियम 14 में नियमों में ढील देने का जिक्र है। नियम 14 भर्ती के नियम के अस्तित्व पर विचार करता है। यदि भर्ती के तीसरे स्रोत का प्रावधान करने वाला ऐसा कोई नियम नहीं है, तो सरकार गैर-मौजूद नियम में ढील नहीं दे सकती। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति को भर्ती का तीसरा स्रोत मानकर गलती की है। भर्ती के स्रोत के रूप में सीधी नियुक्ति और भर्ती के स्रोत के रूप में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के बीच अंतर है। हमारे सामने उद्धृत कुछ मामलों में, स्थानांतरित व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को महत्व दिया गया है। हालाँकि, उन सभी मामलों में, भर्ती का तीसरा स्रोत स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति था। वर्तमान मामले में, उस सीमा तक ऐसा कोई नियम नहीं है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में त्रुटि है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, सुश्री अमृत बराड़ ने 16/17.8.1993 और 11.9.1998 के बीच पंजाब पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति के रूप में 5 साल की सेवा की है। वह निश्चित रूप से इन 5 वर्षों के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेटेज की हकदार हैं। हालाँकि, वह 9.6.1989 और 16/17.8.1993 के बीच की सेवा के वेटेज की हकदार नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए दिया था।

13. तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील आंशिक रूप से स्वीकार कीजाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ममता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***